श्री राधा मोहन सिंह जी

माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री

का

भारत में कृषि ज्ञान प्रबंध पर मार्गदर्शिका के विकास के उद्घाटन

पर संबोधन

समयः 09:15 बजे

दिनांक 28 सितम्बर, 2017

ए. पी. शिंदे हॉल

एनएएससी, नई दिल्ली–110012

सभा में उपस्थित मेरे सहयोगी कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अतिरिक्त सचिव एवं सचिव, भाकृअनुप श्री छबिलेन्द्र राउल जी, वित्त सलाहकार एवं अतिरिक्त सचिव श्री सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, उपस्थित गणमान्य अतिथियों; परिषद के सभी उपमहानिदेशक, सहायक महानिदेशक गण, देश के सभी संस्थानों तथा कृषि विश्वविद्यालयों से आये सभी कृषि ज्ञान प्रबंधन अधिकारी गण, आमंत्रित अतिथि, बहनों और भाइयों।

मित्रों ज्ञान, प्रकाश एवं समृद्धता की ओर एवं अज्ञानता अंधकार की ओर धकेलता है। वैसे तो जहां ज्ञानी समाज सभ्य एवं संपन्न समाज के रूप में जाना जाता है वही अज्ञानता, सामाजिक कुरीतियों एवं बुराईयों को जन्म देती है। भारतीय सभ्यता एवं परंपराओं के विकास में ऋषि मुनियों द्वारा अर्जित एवं संचित ज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

एकलव्य की हड्डी इतनी मजबूत नहीं होती, अर्जुन धुरंधर धनुषधारी नहीं होते, पुष्पक विमान नहीं होता, संजय महाभारत की कथा का सजीव एवं सटीक वृतांत धृतराष्ट्र को न बता पाते, अगर उनके पूर्वजों एवं गुरूओं ने ज्ञान का सृजन कर अपने छात्रों में बांटा नहीं होता।

प्रिय मित्रों एवं बहनों, ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है, इसका इतिहास प्रमाण देता है। रावण का वध नहीं होता और लंका पर विजय नहीं होती, अगर श्री राम जी को इस बात का ज्ञान नहीं कराया जाता कि रावण की नाभि के अमृत को बाण से सुखाना है । दुर्योधन का भी वध नहीं होता अगर भीम को नहीं बताया जाता कि उसका कौन सा अंग कमजोर है एवं वही प्रहार कर उसका वध करना है।

कामधेनु गाय विकसित नहीं होती, भारत एवं लंका के बीच रामसेतु पुल नहीं होता, अगर तैरने वाले पत्थरों के बारे में जानकारी नहीं दी जाती। अगर रामसेतु नहीं बनता एवं लंका पर भी विजय प्राप्त नहीं की जा सकती थी।

दोस्तों एवं मित्रों, भारत की गौरवपूर्ण सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में हमारे मनीषियों ने आबादी से दूर बसे जंगलों एवं गुफाओं में बसे आश्रमों में कठोर तपस्या कर ज्ञान अर्जित किया, तकनीकियों का विकास किया तथा शक्तिशाली समाज की स्थापना की जिसमें नालंदा एवं तक्षशिला जैसे विश्व विख्यात विश्वविद्यालयों की स्थापना की तथा भारत को सोने की चिड़िया वाले देश की पदवी प्रदान कराया।

इतिहास गवाह है चीनी यात्री ह्यून सांग, कोलम्बस तथा वास्को डी गामा भारत में ज्ञान एवं धन अर्जित करने की विद्या और खोज के बारे में इतनी बड़ी–बड़ी यात्राएं की। अगर किसी देश की सभ्यता को कमजोर करना है, कुरीतियों का जाल बिछाना है तो उसके ज्ञान के भंडार को नष्ट कर दिया जाता है। इसी मंशा से ही तक्षशिला एवं नालंदा के विश्वविद्यालयों को नष्ट किया गया।

इतिहास में ये घटनाये ज्ञान के प्रबंधन का देशों की सभ्यताओं के विकास, सामाजिक समरता, आर्थिक संपन्नता, समप्रभुता की रक्षा, खाद्य सुरक्षा के महत्व एवं भूमिका को दर्शाती है।

आधुनिक भारत को कृषि संपन्न देश बनाने में हमारे वैज्ञानिकों, मनीषियों, अनुसंधानकर्त्ताओं ने रात दिन मेहनत कर तकनीकियों व उपयोगी ज्ञान का विकास किया व उनको घर–घर, जन–जन तक पहुंचाकर भारत को कृषि उत्पादन में एक आत्मनिर्भर देश बनाया। आज हम सीनातान कर विश्व को अपनी प्रगति गाथा की गीत सुना रहे है। इसके लिए आप प्रशंसा के पात्र है। जैसे मेरे सहयोगी श्री शेखावत जी ने बताया कि कृषि अनुसंधान परिषद ने अपने जन्म के समय से ही अपने ज्ञान के प्रबंधन क्षेत्र तथा जन–जन तक उसको पहुंचाने में प्रमुख भूमिकाओं का निर्वहन कर देश को अन्न, दूध, फल, मछली, मुर्गीपालन में या तो आत्मनिर्भर बनाया या तो आत्मनिर्भरता के करीब पहुंचाया।

दोस्तों, आईसीटी के प्रचार–प्रसार के बाद ज्ञान संकलन, प्रसंस्करण, वितरण की विधाओं में आमूल–चूल परिवर्तन आये हैं। हमें इन परिवर्तनों को अपनी आवश्यकतानुसार इनकी सदुपयोग कर देश में कृषि में लाभकारी, हितकारी एवं क्रांतिकारी परिवर्तन लाना है।

देश में कृषि प्रचार–प्रसार, अनुसंधान, शिक्षा का एक मजबूत, सशक्त एवं बड़ा संगठनात्मक ढांचा उपलब्ध है। इसमें गांव स्तर, ब्लाक, तहसील तथा जिले स्तर पर प्रादेशिक सरकारों के कृषि विकास अधिकारी, तकनीकी ज्ञान का प्रचार करने हेतु 693 कृषि विज्ञान केन्द्र, परिषद के 103 अनुसंधान संस्थान तथा 73 कृषि विश्वविद्यालय हैं।

शायद ही, पूरे विश्व में, किसी देश के पास इतना मजबूत एवं शक्तिशाली ढांचा उपलब्ध हो। परिषद ने 1994 में प्रोजेक्ट एरिस की स्थापना करना शुरू कर दिया था जिसके तहत इसकी संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों को इंटरनेट युक्त करने का ढांचे तैयार किया गया। उस समय विश्व को कृषि जगत में शायद ही ऐसा कोई पहल या ढांचा का विकास किया होगा। लेकिन मुझे लगता है कि उसके पश्चात् हम अपने आप को विश्व स्तर तक बनाये रखने में सफल नहीं हो सकें। मैंने अनुभव किया है कि अभी भी सूचना

एवं संचार प्रौद्योगिकी, सोशल मीडिया तथा ज्ञान प्रबंधन में बहुत कुछ किया जाना है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि कृषि सुधार में लगे इन सभी घटकों को एक संपर्कसूत्र से जाड़ा जाय और कृषि को लाभदायी तथा देश को सर्वसम्पन्न बनाने में प्रभावशाली कदम उठाया जाय। यह कार्य आधुनिक सूचना एवं संचार का सदुपयोग कर आसानी से किया जा सकता है।

इतनी बड़ी ढांचागत व्यवस्था के बावजूद देश में आंकड़ों की उपलब्धता, रख–रखाव, उनका विश्लेषण कर निष्कर्ष निकालना व ज्ञान में परिवर्तन कर ज्ञानकोष में संग्रह करने की क्षमता में सुधार करने की आवश्यक है। कृषि से जुड़े सभी स्टेकहोल्डर जिसमें वैज्ञानिक विकास अधिकारी तथा किसान भी शामिल हैं, के क्षमता विकास तथा सूचनाओं के आदान–प्रदान के लिए ई–मेल, प्रणाली, फेसबुक, ट्वीअर का सकारात्मक एवं प्रभावी उपयोग किये जाने की आवश्यकता है।

मुझे लगता है कि मंत्रालय एवं आईसीएआर में सूचना तथा संचार प्रणाली में गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन का अभाव है। ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि मैं कार्यालय के सोशल मीडिया सेल को स्थापित करने के लिए बाहर से कर्मचारियों की भर्ती करनी पड़ी।

मैंने आईसीएआर में पारदर्शिता लाने तथा कार्यक्षमता में सुधार के लिए केवीके पोर्टल, आईसीएआर पोर्टल तथा स्टूडेंट पोर्टल को स्थापित करने का अनुरोध किया गया था।

इसमें तो केवीके के पोर्टल तो बन गया है और जिसकी गुणवत्ता में सुधार की भी आवश्यकता है। मुझे अभी भी आईसीएआर तथा स्टूडेंट पोर्टल की पूर्णता, चालू होने का इन्तजार है और इस कार्य को युद्ध स्तर पर किया जाना चाहिए।

आवश्यकता इस बात की है कि विकसित पोर्टल की गुणवत्ता के बारे में सर्वे कर उनको अतः राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया जाये तथा ऐसी व्यवस्था की जाए कि पोर्टल से नाना प्रकार की सूचनाओं के आवश्यकता आधार पर ली जा सके। हमें इस बात का बड़ा पुर्वानुमान करना होगा कि भविष्य में किस तरह की सूचनाये चाहिए। उसके लिए किस तरह के आंकड़ों के संकलन की इलेक्ट्रौनिक व्यवस्था की जानी चाहिए। जिससे हम भविष्य की सूचना व ज्ञान की आवश्यकताओं का पहले ही अनुमान लगा ले और तद्नुसार आंकड़ाकोष बनाना शुरू कर दें।

हमने आईसीएआर को ट्रांसफर व पोस्टिंग के लिए पोर्टल बनाने की बात कही थी, जिसको विकसित कर स्थानांतरण भी किये गये है। इस पोर्टल में भी मानकों, जिसके तहत स्थानांतरण किया जाता है को सार्वजानिक करने, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है जिससे प्रक्रिया के बारे में पूरी व्यवस्था पारदर्शी हो जिससे किसी को भी अनावश्यक लैशमात्र शंका करने का स्थान ना हो।

वैसे तो आईसीएआर के वैज्ञानिकों ने बहुत सारे छोटे–बड़े पोर्टल बनाये तथा कुछ वर्षों तक इसको चालू रखा, लेकिन परियोजना समाप्त होने के बाद कोई भी रख–रखाव तथा उनके प्रबंधन में सुधार करने के बारे में नहीं सोचता। इससे वैज्ञानिकों द्वारा कि गई मेहनत बेकार जाती है तथा लाभार्थियों को इसका लाभ नहीं पहुंच पाता। आवश्यकता इस बात की है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ऐसे बंद पड़े पोर्टलों की समीक्षा करें तथा तुरंत प्रभाव से ऐसे पोर्टलों को किसी एकीकृत एजेंसी जैसे कृषि ज्ञान प्रबंध निदेशालय को देकर चालू करने की व्यवस्था करें। उसी प्रकार भौतिक ढांचे जिसमें अत्याधुनिक कम्प्यूटर सिस्टम जिसमें करोड़ों रुपये लगाये गए है के भी बंद होने की सूचनाएं है। अतः एक लंबी अवधि की नीति बनाकर उन्हें भी चालू रखने के बारे में यह कार्यशाला गंभीर वार्ता कर अपने सुझाव प्रस्तुत करें।

ऐसा भी उदाहारण है कि बड़े–बड़े संसाधन तो खड़े कर लिये जाते है परंतु उनका उपयोग ना के बराबर किया जाता है। यह सरासर जनता के पैसे का दुरूपयोग है। भविष्य में सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि तो भी संसाधन जनता की कमाई से बनाया जाये इनका भरपूर उपयोग हो तथा जनता का भला हो।

देश की भौगोलिक जलवायु , आर्थिक एवं सामाजिक विभिन्नता आधारित कृषि प्रणालियों का विकास कर राष्ट्रीय एवं स्थानीय भाषाओं में ज्ञान का संर्जन कर कृषकों एवं पणधारियों (स्टेकहोल्डर) तक समय से ज्ञान एवं सेवाओं को पहुंचाकर कृषि में संपूर्ण क्रांति लाई जा सकें। हमने बाजारों को खुला एवं पारदर्शी बनाने के लिए ई–नाम पोर्टल की स्थापना की। जिसके तहत एक राष्टीय आफॅनलाइन मंडी विकसित हो सकी। इसी तरह हमारी सरकार ने पशु मंडियों को इलैक्ट्रौनिक करने की पहल कर दी है। देश में कृषि विकास में दिये जाने वाले धन का सही एवं ईमानदारी से उपयोग हो, के लिए हमने भारतीय स्पेस रिसर्च आगो से जीयो टेगिग प्रोजेक्ट आरंभ किया है जिससे पता लगा रहा है सरकारी धन का कितना और किस तरह उपयोग हो रहा है तथा कहां कहां सुविधाओं एवं क्षमताओं का विकास हुआ है।

कृषि आधारित आंकड़ों का इकट्ठा करने, ऑनलाइन प्रकिया, उसके प्रसंस्करण तथा सांख्यिकी विश्लेषण कर सूचना तथा ज्ञान मे परिवर्तित करने की राष्टीय स्तर पर एक कमजोर ढांचा एवं क्षमता है। हमें बिना बिलंब

किये उपलब्ध राष्ट्रीय साधनों का उपयोग करना है तथा जहां कही नहीं है ऐसे संसाधनों का विकास करना है। वैसे तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं कृषि विश्वविद्यालयों ने समकालिन क्षमताओं का विकास किया जाता है लेकिन मुझे लगता है कि हर स्तर पर क्षमताओं का विकास, समृद्ध बनाना तथा मानव संसाधनों को विकसित करने की अत्यंत आवश्यकता है।

जब मैंने मंत्री कार्यालय मैं सोशल मीडिया इकाई की स्थापना शुरू की तो मैंने पाया कि सोशल मीडिया में कृषि को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए मानव संसाधनों की अत्यंत कमी है। अतः मंत्री कार्यालय में सोशल मीडिया इकाई की स्थापना के लिए बाहर से कर्मचारियों की नियुक्ति की हैं । मुझे पता चला है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं कृषि विश्वविद्यालयों के ज्ञान प्रबंधन की नोडल एजेंसी में भी मानव संसाधनों की अत्यंत कमी है। वर्ष 2011 में इस निदेशालय के 57 पदों को मृतप्राय श्रेणी में डाल दिया गया तथा यहां पर 1995 के बाद से वहां किसी तकनीकी अधिकारी एवं कर्मचारी की नियमित नियुक्ति नहीं की गई, जिससे इस निदेशालय में मानव संसाधनों की काफी कमी हो गई है। पिछले सप्ताह ही दिनांक 15 सितम्बर, 2017 को प्रधानमंत्री कार्यालय ने सभी मंत्रालयों जिसमें कृषि मंत्रालय भी शामिल है, को इलैक्ट्रौनिक एवं सोशल मीडिया में किस प्रखरता के साथ अपने मंत्रालय की किया नीतियों, उपलब्धियों तथा लाभाथियों के ज्ञानवर्धन हेतु प्रस्तुत करना है, कि नितियों का उदाहारण सहित उल्लेख है। इसका तुरंत ही अनुपालन होना चाहिए।

यूजीसी द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों के लिए ज्ञान प्रबंधन एवं लाइब्रेरी के लिए INFLIBNET एजेंसी तथा सीएसआईआर ने निस्केयर एजेंसी की स्थापना की। हमारे पास इन दोनों एजेंसियों की संरचनात्मक ढांचा उपलब्ध है। आवश्यकता इस बात की है कि परिषद इनका अध्ययन कर तुरंत प्रभाव से ज्ञान प्रबंधन संगठन में आवश्यकतानुसार मूलभूत परिवर्तन करें तथा इसको इतना सक्षम बनाये कि देश के सभी कृषि संस्थानों तथा कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा सृजन किये जा रहें ज्ञान तथा आंकड़ों का संकलन, प्रसंस्करण, विश्लेषण कर ज्ञान में परिवर्तित कर सभी किसानों, अधिकारियों, नीतिनिर्धारकों, छात्रों एवं वैज्ञानिकों को उनकी आवश्यकतानुसार ऑनलाइन सूचना एवं ज्ञान उपलब्ध करा सकें।

धन्यवाद!